भारतीय वैश्विक परिषद

सप्रू हाउस

****

'न्यूक्लियर फ्लक्स: वैश्विक राजनीति की बदलती गतिशीलता' पर आईसीडब्ल्यूए पैनल चर्चा की प्रतिलिपि, सप्रू हाउस, 24 सितंबर 2025

मुकेश कुमार: नमस्कार, महानुभावों, देवियो एवं सज्जनो। मुझे भारतीय वैश्विक परिषद में "न्यूक्लियर फ्लक्स: वैश्विक राजनीति की बदलती गतिशीलता" विषय पर आयोजित इस पैनल चर्चा में आप सभी का स्वागत करते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया अपने फ़ोन साइलेंट मोड पर रखें। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम की शुरुआत आईसीडब्ल्यूए की कार्यवाहक महानिदेशक एवं अपर सचिव सुश्री नूतन कपूर महावर के स्वागत भाषण से होगी। पैनल चर्चा की अध्यक्षता निरस्त्रीकरण सम्मेलन में भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत राकेश सूद करेंगे। इसके अलावा, आज हमारे साथ तीन सम्मानित पैनलिस्ट भी हैं। हमारे पहले पैनलिस्ट प्रो. राजेश राजगोपालन, प्रोफेसर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, संगठन एवं निरस्त्रीकरण केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, हैं, और उनके बाद मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान के वरिष्ठ शोध सहयोगी डॉ. राजीव नयन हैं। और हमारी अंतिम वक्ता प्रो. रेशमी काज़ी, राजनीति विज्ञान विभाग, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली हैं। चर्चा के पश्चात् थोड़ी देर के लिए प्रश्नोत्तर सत्र होगा, जिसका संचालन अध्यक्ष महोदय करेंगे। इसके साथ ही, अब मैं आईसीडब्ल्यूए की कार्यवाहक महानिदेशक सुश्री नूतन कपूर महावर से अनुरोध करता हूँ कि वे कृपया अपना स्वागत भाषण दें।

नूतन कपूर महावर: राजदूत सूद, प्रतिष्ठित विशेषज्ञों, छात्रों व मित्रों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की दुनिया में परमाणु हथियार वैश्विक सुरक्षा ढांचे का एक अहम और निर्णायक हिस्सा रहे हैं। 1945 से, परमाणु हथियारों से जुड़े नैरेटिव व सिद्धांतों ने निवारण, यानी परमाणु हथियारों को युद्ध में 'इस्तेमाल' किए जाने वाले हथियार के रूप में नहीं, बल्कि 'उनके इस्तेमाल की धमकी' से युद्ध को 'रोकने' वाले हथियार के रूप में; और उनके आकस्मिक या इरादतन इस्तेमाल के बीच विरोधाभास पर ज़ोर दिया है। इसके विनाशकारी परिणामों को मानते हुए, ये नैरेटिव और सिद्धांत इस धारणा पर टिकें हैं कि परमाणु हथियार स्थिरता ला सकते हैं। वैश्विक स्तर पर मौजूदा भू-राजनीतिक अशांति अब इन नैरेटिव और सिद्धांतों के लिए चुनौती बन रही है, क्योंकि परमाणु को लेकर बयानबाज़ी बढ़ती जा रही है, वैश्विक अप्रसार एवं हथियार नियंत्रण ढाँचे से संबंधित समझौते टूट रहे हैं, और सुरक्षा संबंधी रुख़ में बदलाव हो रहे हैं।

भेदभाव से भरी परमाणु अप्रसार संधि, एनपीटी, जिस पर भारत ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था, दुनिया को परमाणु संपन्न एवं परमाणु विहीन देशों में बांटने का प्रयास करती थी। आज इसको लेकर गंभीर चुनौतियां आ रही हैं। शुरुआत में पी5 तक सीमित, परमाणु संपन्न देशों की संख्या दशकों में सुरक्षा संबंधी दुविधाओं के बढ़ने के साथ-साथ बढ़ती गई। सुरक्षा को मुश्किल माहौल, जिसमें शत्रुतापूर्ण चीन-पाक गठजोड़ भी शामिल था, के कारण भारत ने अपनी रक्षा हेतु परमाणु हथियार विकसित किए। पाकिस्तान ने भारत के साथ बराबरी की चाह में परमाणु हथियारों को बनाया। पाकिस्तान बस हमारी नकल करता रहा, कभी हमारा अनुसरण करता रहा, तो कभी शह-मात का खेल खेलता रहा। इज़राइल द्वारा शक्ति के साधन के रूप में परमाणु हथियारों को बनाने के आधार को बढ़ती स्वीकृति के उलट तर्क का शिकार होना पड़ा। हालांकि, असुरक्षित अनुभव करने वाले डीपीआरके के कार्यों को कभी महत्वाकांक्षा के रूप में देखा गया, तो कभी अनिश्चित व्यवहार के रूप में। इस्लामी दुनिया की जटिल गतिशीलता और ईसाई दुनिया के साथ उसके जुड़ाव ने ऐसे ईरान को जन्म दिया जो यह तय नहीं कर पा रहा था कि वह किस तरफ रहना चाहता है।

हाल के संघर्षों में परमाणु को लेकर तीखी बयानबाजी देखी गई है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने परमाणु खतरों को लेकर चर्चा को फिर से शुरू कर दिया है, जबकि ईरान-इज़राइल टकराव, उत्तर कोरिया की परमाणु महत्वाकांक्षाएँ, और परमाणु ढाल के पीछे पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को बढ़ावा देना और पोषित करना हमें ऐसी बयानबाज़ी से जुड़े जोखिमों की याद दिलाता है। आईएनएफ के पतन और नई एसटीएआरटी संधि को लेकर अनिश्चितता ने महाशक्तियों के बीच बढ़ते अविश्वास के दौर में हथियारों पर नियंत्रण की कमी को उजागर किया है।

मित्रों, कुल मिलाकर, परमाणु हथियार एक बार फिर रणनीति एवं राजनीतिक बयानों, दोनों में तेजी से उभर रहे हैं। रणनीतिक स्थिरता को लेकर बढ़ती चिंताओं एवं गलत आकलन या अनपेक्षित प्रसार के बढ़ते जोखिम के साथ, वैश्विक परमाणु राजनीति और भी अस्थिर हो गई है। विगत एक दशक में अमेरिका और रूस जैसी प्रमुख शक्तियों के परमाणु सिद्धांत क्षेत्रीय या पारंपरिक संघर्षों में परमाणु हथियारों के संभावित उपयोग पर अधिक ज़ोर देने लगे हैं। यूएस न्यूक्लियर पोस्चर रिव्यू 2010-18-22 ने परमाणु हथियारों की भूमिका को बढ़ाते हुए इसमें व्यापक निवारण को भी शामिल कर दिया, जबकि रूस के सैन्य सिद्धांत ने परमाणु व पारंपरिक युद्ध के बीच की रेखाओं को धुंधला कर दिया है। मित्रों, इन बदलावों ने परमाणु उपयोग की सीमा को कम कर दिया है, अविश्वास को बढ़ाया है, और दुनिया में परमाणु हथियारों की होड़ के फिर से शुरू होने की संभावना को बढ़ा दिया है।

आज, निवारण का पारंपरिक मॉडल, जो सेकेंड-स्ट्राइक की विश्वसनीय क्षमता पर निर्भर करता था, कम स्थिर है और दबाव में है क्योंकि देश पूरी तरह से रक्षात्मक रुख अपनाने के बजाय बल प्रयोग, अस्थिरता एवं सामरिक परमाणु विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। गैर-सरकारी तत्व, सैन्य व सत्तावादी नेतृत्व की कार्य शैली निवारण की अवधारणा को मुश्किल बना रही हैं। इसके अलावा, जैसा कि मैंने अभी कहा, सामरिक

परमाणु हथियारों ने पारंपरिक एवं परमाणु युद्ध के बीच के अंतर को कम कर दिया है। युद्धक्षेत्रों में इनके संभावित उपयोग से परमाणु युद्ध की तीव्रता कम हो जाती है और संकट से निपटना मुश्किल हो जाता है। यह अस्पष्टता सीमित युद्धों को पहले से कहीं अधिक जोखिमपूर्ण और विनाशकारी बना सकती है। सबसे अहम बात, परमाणु सामग्री या सामरिक परमाणु हथियारों के आतंकवादियों के हाथों में पड़ने का खतरा वास्तक में है, खासकर कमज़ोर देशों में।

वैश्विक परमाणु अप्रसार की संरचना मूलतः "सिक्योरिटी की गारंटी" की नींव पर टिकी है। जैसा कि मैंने कहा, शस्त्र नियंत्रण संधियाँ, जिनमें से कई अब खत्म हो रही हैं, हमेशा से "आश्वासन" पर आधारित रही हैं।

इसी तरह, परमाणु हथियार-मुक्त क्षेत्रों को उनकी वैधता एवं प्रभावशीलता उनके भागीदार देशों को दी गई "सिक्योरिटी गारंटी" से मिलती है। एनपीटी के मूल में एक बड़ा समझौता, अंतर्निहित समझ निहित है कि परमाणु हथियार संपन्न देश गैर-परमाणु हथियार संपन्न देशों की सुरक्षा करेंगे, बशर्ते कि उन्हें उनके व्यवहार में बदलाव न दिखे। हालाँकि, आज की दुनिया में, जहाँ अनिश्चितता बहुत अधिक, परमाणु हथियारों पर फिर से ज़ोरदार बयानबाज़ी, युद्ध, ज़बरदस्ती व भय के हथियार के रूप में परमाणु हथियारों को सामान्य मानने की चिंताजनक स्थिति है, और दुनिया के बढ़े देश तीसरे विश्व युद्ध के बारे में खुलकर बोलने लगे हैं, ऐसे में "सिक्योरिटी की गारंटी" कौन या क्यों देगा? और इससे भी अहम बात यह है कि ऐसे में सवाल उठता है कि दुनिया में ऐसे माहौल में, जहाँ पुराने मानदंड बिखर रहे हैं और निवारण-आधारित स्थिरता पर भारी दबाव है, सिक्योरिटी की गारंटी क्या होगी।

अंत में, क्या मैं यह कहना चाहूंगी कि अगर कोई ऐसा परमाणु हथियार जो "सिक्योरिटी की सबसे अधिक गारंटी" और "करेंसी ऑफ पावर" है, तो उसे पाने की इच्छा से किसी को कैसे रोका जा सकता है? जब तक कि दुनिया ऐसे सुरक्षा समझौते पर न पहुँच जाए जो उन्हें किसी भी तरह से शक्ति का स्रोत मानने से अवैध न ठहरा दे। ऐसी दुनिया के लिए जो सबसे घातक, सटीक एवं सामूहिक हथियारों से पूरी तरह लैस है, जो समझौते से ज़्यादा नफ़रत हेतु प्रवृत्त है, जहाँ नेतृत्व हमेशा बुद्धिमत्ता से नहीं होता, और जो भूगर्भीय बदलावों से गुज़र रही है, इससे ज़्यादा यथार्थवादी परिदृश्य क्या हो सकता है? ऐसा तृतीय विश्व युद्ध जिसमें प्रतिरोध विफल हो और परमाणु हथियार युद्ध के हथियार हों। ऐसा तृतीय विश्व युद्ध जहाँ प्रतिरोध किसी तरह कायम रहे। नए ज़माने का वैश्विक सुरक्षा समझौता जिसमें तृतीय विश्व युद्ध न हो या ऐसा नए ज़माने का वैश्विक सुरक्षा समझौता जिसके पहले सभी युद्धों की जननी, तृतीय विश्व युद्ध हो। तो बड़ा सवाल यह है कि हम वर्तमान परमाणु प्रवाह से कैसे उबरें ताकि ऐसी व्यवस्था बहाल हो सके जैसी व्यवस्था कुछ चाहते हैं, या नई विश्व व्यवस्था का सृजन कैसे करें जैसा कि दूसरे इसे देखते हैं? मैं यहाँ एआई फैक्टर का भी ज़िक्र करना चाहूँगी जो अस्थिरता में नए जोखिम पैदा करता है, और कहना चाहूँगी कि एक-दूसरे को चोट पहुँचाने और नुकसान पहुँचाने हेतु बनाई गई विश्व व्यवस्था अनुपयोगी हो गई है, और मानव जाति की प्रोग्रामिंग में ही बुनियादी बदलाव की ज़रूरत है। मैं इसपर अच्छे विचार रखते हुए चर्चा की उम्मीद करती हूँ, और पैनलिस्टों को शुभकामनाएँ देती हूँ।

मुकेश कुमार: धन्यवाद महोदया। अब मैं राजदूत राकेश सूद से अनुरोध करता हूँ कि वे अपना वक्तव्य दें और आगे की कार्यवाही का संचालन करें।

राकेश सूद: धन्यवाद। मुकेश, धन्यवाद। और मैं आईसीडब्ल्यूए को इस सत्र की अध्यक्षता हेतु आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद देता हूँ, और खासतौर पर सुश्री नूतन महावर को, जिन्होंने बहुत ही सोच विचार कर... परमाणु व्यवस्था की वर्तमान स्थिति पर एक मंच तैयार किया। आप जानते हैं, कुछ मायनों में, आज के कार्यक्रम का शीर्षक, जो परिवर्तनशीलता एवं फिर बदलती गतिशीलता के बारे में है, मूल मुद्दे की ओर इशारा करता है, क्योंकि अगर आप मौजूदा व्यवस्था को देखें, तो कह सकते हैं कि यह व्यवस्था बेहद सफल रही है। हथियार नियंत्रण प्रणाली और इस तरह की चीज़ों को, अगर आप दुनिया में मौजूद लगभग 65,000 परमाणु बमों की संख्या के संदर्भ से देखें, या उस समय सिर्फ़ अमेरिका व सोवियत संघ के बीच, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी संख्या में परमाणु हथियार थे। वहाँ से, आज हम सभी परमाणु हथियार संपन्न देशों को मिलाकर लगभग 15,000, 16,000 तक पहुँच गए हैं, जो कि एक जबरदस्त कमी है। मेरा मतलब है, आज 75 प्रतिशत परमाणु बम या तो कहीं सुरक्षित रखे हुए हैं या नष्ट कर दिए गए हैं। अगर हम एनपीटी पर गौर करें, जिसका ज़िक्र तब हुआ था जब इसकी शुरुआत हुई थी, जब इसे पहली बार 1970 में हस्ताक्षर हेतु रखा गया था... 1968, शायद, लगभग 45-50 देशों ने ही इस पर हस्ताक्षर किए थे। आज, सभी देश इसके पक्षकार हैं, 190 से ज़्यादा, सिवाय चार देशों के जो इससे बाहर हैं, यानी भारत, पाकिस्तान, इज़राइल और उत्तर कोरिया। इसके अलावा, हर कोई इसमें भागीदार है। तो यह एक बड़ी सफलता है। जब यह 1970 में लागू हुआ, तो यह एक संधि थी जो 25 साल तक लागू रहने वाली थी, और उसके बाद, इसको आगे जारी रखने को लेकर फैसला लिया जाना था। 1995 में, हमने देखा कि इसे हमेशा के लिए बढ़ा दिया गया। यह एक बड़ी उपलब्धि थी। 1945 में, या 60 के दशक में भी, जब एनपीटी पर बातचीत चल रही थी, अगर कोई कहता कि ठीक है, अगले 50 सालों में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि लोग इस पर यकीन करते। लेकिन सच्चाई यह है कि 1945 के बाद से, हमने देखा है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ है। यह भी एक बड़ी उपलब्धि है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए, इन सब बातों से, हम सभी को संतुष्ट और खुश होना चाहिए कि परमाणु हथियार नियंत्रण व्यवस्था, या परमाणु अप्रसार व्यवस्था, ये सभी काफी सफल रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसा नहीं है। दरअसल, ज़्यादा से ज़्यादा टिप्पणीकार, विश्लेषक, राजनीतिक नेता, रणनीतिक विश्लेषक इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि जोखिम बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है, और कार्यवाहक महानिदेशक ने इस बात को पूरी तरह से सामने रखा है। और इसका कारण यह है कि परमाणु व्यवस्था को आकार देने वाली अंतर्निहित राजनीति ध्वस्त हो गई है। वह द्विध्रुवीय दुनिया, अमेरिका-सोवियत संघ, दो परमाणु महाशक्तियाँ, मेरा मतलब है, मूलतः यही वह व्यवस्था थी जिसने परमाणु अप्रसार व्यवस्था, शस्त्र नियंत्रण व्यवस्था, आदि की दुनिया को आकार दिया। और चूँकि वह व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, और हम वास्तव में नहीं जानते कि नई भू-राजनीतिक व्यवस्था क्या है, और इसीलिए इसे परिवर्तनशीलता कहा जाता है। इसलिए, पुरानी व्यवस्था, जिसमें परमाणु व्यवस्था भी शामिल है, दबाव में है। और हम पाते हैं कि इसके अलावा, कई तकनीकी विकास भी हुए हैं जिन्होंने परमाणु

हथियारों की भूमिका को बदल दिया है। यह हम पर, पैनलिस्टों और आप पर निर्भर है कि हम पूछें कि इसमें क्या बदलाव आया है? और यदि हाँ, तो किस तरह से? क्या परमाणु हथियार अभी भी उतने ही विनाशकारी हैं? क्योंकि आज, देश अधिक से अधिक इस्तेमाल करने योग्य परमाणु हथियारों की तलाश में हैं। और मिसाइल रक्षा के क्षेत्र में भी विकास हो रहा है। कम क्षमता वाले परमाणु हथियारों के क्षेत्र में विकास हो रहा है, हाइपरसोनिक हथियारों के क्षेत्र में विकास हो रहा है, इत्यादि। तो क्या पहले की सटीक वैश्विक प्रहार क्षमताएँ, निवारण को कमजोर करती हैं? क्या ये परमाणु निवारण को मज़बूत करते हैं? क्या ये परमाणु हथियारों को ज़्यादा उपयोगी, कम उपयोगी या निरर्थक बनाते हैं? सच कहूँ तो, कोई नहीं जानता। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि इसके साथ ही, एक चिंता यह है कि अगर हमने 1945 से, यानी 80 सालों से, परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं देखा है, तो क्या हम निश्चित हो सकते हैं कि अगले 80 सालों में भी हम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं होगा? मुझे पता है कि मैं अगले 80 सालों तक दुनिया में नहीं रहूँगा। लेकिन मुझे यकीन है कि यहाँ बहुत सारे युवा हैं जो रहेंगे। और मैं उनकी खातिर उम्मीद करता हूँ कि हम यही स्थिति बनाए रख पाएँगे। दुर्भाग्य से, निषेध परमाणु व्यवस्था का सबसे कमज़ोर कानूनी हिस्सा है। क्योंकि अप्रसार व्यवस्था ने परमाणु हथियारों के प्रसार को अवैध तो कर दिया, लेकिन उसने परमाणु हथियारों को अवैध नहीं बनाया। इसलिए प्रतिबंध संधि के अलावा कोई भी अंतरराष्ट्रीय संधि नहीं है जो परमाणु हथियारों को अवैध ठहराती हो। लेकिन विडंबना यह है कि 2017 में अस्तित्व में आई इस प्रतिबंध संधि पर किसी भी ऐसे देश ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं या जो अपनी सुरक्षा हेतु परमाणु हथियारों पर निर्भर हैं। फिर भी, यह एक मानक ढाँचा ज़रूर तैयार करती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के संदर्भ में इसका महत्व होगा या नहीं, यह देखना बाकी है। तो इसके साथ ही, मैं पैनलिस्टों को अपनी शुरुआती टिप्पणियाँ देने के लिए आमंत्रित करता हूँ। हम प्रोफेसर राजगोपालन से शुरुआत करेंगे, उसके बाद डॉ. नयन और फिर प्रोफेसर रेशमी काज़ी। आप सभी का समय आठ से दस मिनट का होगा।

राजेश राजगोपालन: धन्यवाद, राजदूत। शुक्रिया, राजदूत सूद, और हमें आमंत्रित करने हेतु आईसीडब्ल्यू और श्रीमती महावर का भी धन्यवाद। रेशमी व राजीव जी के साथ पैनल में शामिल होना मेरे लिए सम्मान की बात है क्योंकि हम वास्तविक हैं, शायद नहीं, लेकिन हम सभी आईडीएसए के परमाणु समूह का हिस्सा थे। और खासकर यह जगह, क्योंकि आईडीएसए यहीं हुआ करता था। मैं अपने एक छात्र को, जो मेरे साथ ही यात्रा कर रहा था, बता रहा था कि आईडीएसए इसी इमारत के दूसरी तरफ़ हुआ करता था, यानी, एनेक्स में। गंदा, घिनौना, लेकिन हमने खूब मज़े किए। तो फिर भी, मुझे लगता है, हमें आमंत्रित करने हेतु आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इससे बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गईं, लेकिन दुर्भाग्य से मैंने आपको यह भी बताया कि मैं कितना बूढ़ा हूँ, लेकिन, कोई बात नहीं। लेकिन, जैसा कि आप जानते हैं, परमाणु हथियारों और वैश्विक राजनीति को देखते हुए, मुझे लगता है कि मुझे "वैश्विक राजनीति की बदलती गतिशीलता" शीर्षक, या उपशीर्षक, पसंद आया, क्योंकि ज़ाहिर है कि आप परमाणु हथियारों को अलग-थलग करके नहीं देख सकते, आपको परमाणु हथियारों को राजनीति के संदर्भ में भी देखना होगा। जैसा कि राजदूत सूद ने बताया, हमें इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है कि भविष्य में ये चीज़ें कैसे सामने आएंगी, लेकिन मैं बस चार बातें सामने रखना चाहता हूँ कि आने वाले दशकों में मैं इनमें से कुछ घटनाक्रमों

को कहाँ देखता हूँ। पहला यह कि ज़ाहिर है कि हम विगत 30 सालों से जिस वैश्विक व्यवस्था को देखते आ रहे हैं, उससे बिल्कुल अलग एक अलग वैश्विक व्यवस्था उभरती हुई दिख रही है। हम एक द्विध्रुवीय और एकध्रुवीय दुनिया से एक अन्य द्विध्रुवीय युग में प्रवेश कर रहे हैं। मुझे पता है कि हम, कम से कम दिल्ली में, यह सोच रहे हैं कि उभरती हुई व्यवस्था बहुध्रुवीय व्यवस्था होगी। मुझे इस संभावना पर गहरा संदेह है कि यह बहुध्रुवीय व्यवस्था होगी। यह द्विध्रुवीय व्यवस्था होगी, इसका सीधा सा कारण यह है कि, ध्रुवीकरण को शक्ति के संदर्भ में मापा जाता है, और केवल दो देश ही हैं जो बाकियों से कहीं आगे हैं। धन शक्ति का एक पैमाना है, अमेरिका का सकल घरेलू उत्पाद लगभग 30 ट्रिलियन है, चीन का लगभग 20 ट्रिलियन है, और हमारा, मुझे नहीं पता, लगभग 4 ट्रिलियन है। तो कोई नहीं है, और रूस 2 ट्रिलियन से कम है, तो हम, मेरा मतलब है, जब आप ध्रुवीकरण को मापते हैं, तो आप न केवल शक्ति के संदर्भ में मापते हैं, बल्कि यह भी देखते हैं कि अंतर कितना है, अंतर क्या है, और इसलिए यह अंतर इतना बड़ा है कि मुझे निकट भविष्य में बहुध्रुवीयता उभरती हुई नहीं दिखती। तो, मूलतः हम द्विध्रुवीय विश्व की बात कर रहे हैं, और वह द्विध्रुवीय विश्व, कई मायनों में, 1945-1991 की अवधि के द्विध्रुवीय विश्व के समान ही होगा, जिसमें मूलतः ये दो शक्तियां, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन, बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा करेंगी, और वे पूरे विश्व में प्रतिस्पर्धा करेंगी, यह मानते हुए कि उन दोनों के पास उस तरह की शक्ति है, लेकिन इसमें कुछ वैचारिक पहलू भी होंगे, भले ही यह केवल पश्चिम बनाम पूर्व हो सकता है, मेरा मतलब है, यह साम्यवाद बनाम पूंजीवाद नहीं होगा, और निश्चित रूप से, पिछली द्विध्रुवीय व्यवस्था से असमानताएं होंगी, इस अर्थ में कि वर्तमान द्विध्रुवीय व्यवस्था में, दोनों ध्रुवीय शक्तियां आर्थिक रूप से गहराई से जुड़ी हैं, जो स्पष्ट रूप से पिछली व्यवस्था में नहीं है। इसलिए कुछ विशिष्टताएँ अलग होंगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, क्योंकि ज़ाहिर है, महाशक्तियाँ द्विध्रुवीय काल के आने से पहले और 1945 से पहले भी प्रतिस्पर्धा करती थीं, और उन मामलों में भी, कई मामलों में, वे आर्थिक रूप से गहराई से एकीकृत थीं, फिर भी, प्रतिस्पर्धा जारी रही। लेकिन एक और अहम बात यह भी है कि यह अलग होगा, वह यह कि चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका के मुकाबले सोवियत संघ से कहीं ज़्यादा, कहीं ज़्यादा धनी और कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है। चीन का सकल घरेलू उत्पाद संयुक्त राज्य अमेरिका का लगभग दो-तिहाई या तीन-चौथाई है, जबकि क्रय शक्ति समता की बात तो छोड़ ही दीजिए, विनिमय दर के लिहाज से भी, सोवियत संघ कभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका के 50% से आगे नहीं बढ़ पाया, और इस लिहाज से, चीन सोवियत संघ की तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका का कहीं अधिक शक्तिशाली, कहीं अधिक सक्षम प्रतिद्वंद्वी है, और इसलिए, अभी तक इसे पूरी तरह से सैन्य दृष्टि से नहीं बदला गया है, लेकिन इसे बदला जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं, पिछले छह महीनों में, नए लड़ाकू विमानों की संख्या, और नई तकनीकों की संख्या जो चीन ला रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा एकमात्र देश है जिसके पास दो पाँचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा एकमात्र देश है जिसके पास पाँचवीं पीढ़ी का बमवर्षक विमान है, जो काफी आश्चर्यजनक था। और निश्चित रूप से, वे अपने परमाणु शस्त्रागार में बिना किसी कारण के बड़े पैमाने पर वृद्धि कर रहे हैं, मुझे लगता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ समानता के अलावा। और इसलिए दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग समूहों का मानना है कि वे लगभग 1,000 पर रुक जाएँगे, जिस पर मुझे गहरा संदेह है, क्योंकि मुझे लगता है कि वे राजदूत सूद द्वारा पहले बताई गई संख्या से मेल खायेगा, जो लगभग 3,500, 4,000 है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका

और रूस की संख्या है। इसलिए मुझे लगता है कि इसका मुख्य उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बराबरी करना है। और इसका मतलब होगा इतनी बड़ी परमाणु शक्ति होना। इसलिए यह सोवियत संघ की तुलना में कहीं अधिक सक्षम सैन्य शक्ति होगी। और इन सबका मतलब यह है कि प्रतिस्पर्धा संभवतः अमेरिका-सोवियत प्रतिस्पर्धा, अमेरिका-सोवियत द्विध्रुवीय काल की तुलना में कहीं अधिक तीव्र होगी। लेकिन कुछ अंतरों की बात करें तो, मेरा मतलब है कि ये युग बिल्कुल एक-दूसरे के समान नहीं हैं, ज़ाहिर है। साझा बाज़ार या इस तथ्य के अलावा कि वे दोनों एक वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली का हिस्सा हैं, मुझे लगता है कि पिछले शीत युद्ध काल से एक और अंतर यह है कि चीन गठबंधनों में, कम से कम औपचारिक गठबंधनों में, रुचि नहीं रखता है। मेरा मतलब है, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया जैसे देशों के साथ उसका सुरक्षा सहयोग तो साफ़ है, लेकिन कोई औपचारिक गठबंधन नज़र नहीं आता। शायद इसमें कोई बदलाव आए। हमें नहीं पता। लेकिन कम से कम अभी तक तो कोई औपचारिक गठबंधन नहीं है। और इसी तरह, संयुक्त राज्य अमेरिका भी औपचारिक गठबंधन करने को लेकर बहुत अनिच्छुक नज़र आता है। दरअसल, पिछले हफ़्ते तक, जब सऊदी अरब और पाकिस्तान ने सैन्य गठबंधन करने का फ़ैसला किया, तब तक हमारे बीच काफ़ी समय से कोई नया सैन्य गठबंधन नहीं हुआ था। लेकिन इसकी सबसे अजीब बात यह है कि आजकल औपचारिक सैन्य गठबंधन होना बहुत असामान्य बात है। इस लिहाज़ से, विश्व व्यवस्था अपने आप में कुछ अलग है, लेकिन पिछली द्विध्रुवीय व्यवस्था से इसमें समानताएँ हैं।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा वह यह है कि इस तरह की द्विध्रुवीय व्यवस्था में परमाणु हथियारों की क्या भूमिका है? मेरा मतलब है, मुझे लगता है, जैसा कि मैं पहले कह रहा था, परमाणु समता की पूरी संभावना है। लेकिन परमाणु समता एक अजीब स्थिति भी पैदा करेगी, यानी आपके पास परमाणु द्विध्रुवीयता नहीं, बल्कि परमाणु त्रिध्रुवीयता होगी। क्योंकि ज़ाहिर है, रूस एक महाशक्ति इसलिए है क्योंकि उसके पास परमाणु हथियार हैं। और इसलिए वे परमाणु हथियारों को छोड़ने वाले नहीं हैं। मुझे लगता है कि पुतिन ने कल मौजूदा एसटीएआरटी संधि को आगे बढ़ाने का सुझाव इसलिए दिया क्योंकि वे मानते हैं कि अगर संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन हथियारों की होड़ में आगे बढ़ते हैं तो रूस शायद प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा। और इसलिए मुझे लगता है कि वे ऐसा कर रहे हैं, रूस इस संभावना के प्रति या परमाणु हथियार नियंत्रण समझौते हेतु थोड़ा और खुला हो सकता है क्योंकि इससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी एक ही तरह बिंदु पर रहें। लेकिन मुझे लगता है कि चीन एक समस्या है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि चीन उस तरह के परमाणु समझौते की अनुमति देगा, जब तक उसके पास पर्याप्त हथियार, पर्याप्त परमाणु हथियार न हों। लेकिन एक अन्य कारण यह भी हो सकता है कि ट्रम्प जिस गोल्डन डोम मामले की बात कर रहे हैं, मुझे संदेह है कि किसी भी तरह का वैश्विक, किसी भी तरह का व्यापक या राष्ट्रव्यापी मिसाइल रक्षा कार्यक्रम संभव है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पुतिन यह जानना चाहेंगे कि इसकी संभव है या नहीं। तीसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा वह यह है कि स्थिरता हेतु इन सबका क्या अर्थ है? दोनों राजदूतों ने अपने शुरुआती प्रस्तुतियों में जो बिंदु उठाए थे, उनमें से एक। क्या यह परमाणु वृद्धि को रोकता रहेगा? क्या परमाणु हथियार परमाणु वृद्धि को रोकते रहेंगे? ज़ाहिर है, मुझे लगता है कि यह एक उम्मीद बनी हुई है और मैं नहीं कह रहा हूँ, ज़ाहिर है, दो प्रमुख संकट, यूक्रेन एक है, लेकिन ज़ाहिर है कि ताइवान एक

अन्य महत्वपूर्ण संकट है जो उभरने वाला है। ताइवान में कौन किसे रोकेगा, यह देखना बाकी है क्योंकि ताइवान को पारंपरिक अर्थों में भी पछाड़ना आसान नहीं है। जल-थल अभियान सबसे कठिन सैन्य अभियान होते हैं जो कोई भी देश, कोई भी सेना कर सकती है। और ताइवान का भूभाग आसानी से आक्रमण करने हेतु उपयुक्त नहीं है। ये सभी उपाय चीन के लिए औपचारिक आक्रमण के लिए पर्याप्त निवारक होने चाहिए, लेकिन हम नहीं जानते। लेकिन अगर आक्रमण होता है, तो उसका समाधान कैसे होगा, क्योंकि अमेरिका इसमें शामिल होगा या नहीं, और चीन अमेरिका को रोक पाएगा या नहीं, यह एक सवाल बना हुआ है, क्योंकि चीन का निवारक सिर्फ़ परमाणु नहीं है, बल्कि यह पारंपरिक भी है क्योंकि उनके पास जहाज-रोधी बैलिस्टिक मिसाइलें वगैरह हैं। इसलिए यह एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या परमाणु निवारक क्षेत्रीय स्तर पर, यानी भारत, पाकिस्तान, ईरान, इज़राइल, सऊदी अरब, इन सभी मामलों में, संभवतः यूरोप में भी, कारगर हो सकता है। छोटे परमाणु बल बड़े परमाणु बलों की तुलना में कुछ हद तक ज़्यादा स्थिर होते हैं, जैसे कि शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा बनाए गए थे, सिर्फ़ इसलिए कि उन्हें छोटे परमाणु बलों के साथ उसी तरह के जोखिम भरे कमांड और नियंत्रण ढाँचों की ज़रूरत नहीं होती। आप अपना समय ले सकते हैं और आपके पास बेहतर, कहीं ज़्यादा ढीली कमान एवं नियंत्रण प्रणालियाँ हो सकती हैं, या कम से कम ज़्यादा ढीली नहीं, बल्कि कम से कम ज़्यादा शिथिल कमान और नियंत्रण प्रणालियाँ हो सकती हैं। और इससे ज़्यादा स्थिरता सुनिश्चित होगी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि परमाणु हथियार ही अंततः स्थिरता सुनिश्चित करेंगे। इसलिए यह ऐसा सवाल है जिस पर हमें इंतज़ार करना होगा और देखना होगा। जब परमाणु निवारण की बात आती है तो मैं आशावादी हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि देश, ख़ासकर नेता, हमारी सोच से कहीं ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं, और इसलिए परमाणु निवारण कायम रहेगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं इस बारे में ज़्यादा ग़लत नहीं हूँ। एक अंतिम बात, कि इन सबका प्रसार के संदर्भ में क्या अर्थ है? मुझे लगता है कि ऐसी संभावना है कि प्रसार को और बढ़ावा मिलेगा क्योंकि दोनों राजदूतों ने जिस संपूर्ण परमाणु अप्रसार व्यवस्था की बात की थी, वह समय के साथ कमज़ोर पड़ सकती है। चीन का इसमें कोई वास्तविक हित नहीं है। लेकिन कोई यह भी तर्क दे सकता है कि चीन का इसमें हित है क्योंकि चीन नहीं चाहता कि उसके आसपास ज़्यादा से ज़्यादा परमाणु शक्तियाँ हों। तो हो सकता है, हो, लेकिन बहुत कुछ चीन के रवैये पर निर्भर करेगा। अब तक, वे इस पूरे मुद्दे पर कुछ हद तक अस्पष्ट रहे हैं। जैसा कि राजदूत सूद ने बताया, उन्होंने मूल रूप से एनपीटी का समर्थन नहीं किया था, बहुत कम देश मूल रूप से एनपीटी व्यवस्था का समर्थन करते थे। चीन ने तो बिल्कुल नहीं किया था। चीन, शायद 1992 तक? जब उन्होंने अंततः एनपीटी को स्वीकार किया। फ्रांस ने भी ऐसा नहीं किया था। 1992 में भी। इसलिए फ्रांस और चीन का मानना था कि प्रसार वास्तव में एक अच्छी बात है। लेकिन फिर चीन का पाकिस्तान के परमाणु विकास में भी हाथ रहा है, पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार को विकसित करने में, इन सबमें। इसलिए वे कुछ हद तक अस्पष्ट रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उन्हें परमाणु प्रसार को रोकने में कुछ लाभ दिखाई दे, क्योंकि यह है ही नहीं, इसमें उनकी हिस्सेदारी है। लेकिन परमाणु प्रसार का एक दूसरा पहलू, जिसका मैं ज़िक्र करना चाहूंगा, वह यह भी है कि अमेरिकी प्रतिबद्धताओं का क्या होता है, है ना? मेरा मतलब है, कई देश, जो परमाणु हथियार बना सकते थे, परमाणु हथियार नहीं बना पाए हैं, इसका एक कारण यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने उनकी रक्षा की है। अमेरिका के विस्तारित निवारण ने उनकी रक्षा की है। अगर अमेरिका, जैसा

कि हम ट्रंप के कार्यकाल में देख रहे हैं, और शायद यह अमेरिकी विदेश नीति का एक हिस्सा बन जाएगा, अगर अमेरिका अब अपने सहयोगियों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं रहेगा, तो उसके सहयोगियों को खुद ही अपनी चिंता करनी होगी, जिसका मूलतः मतलब है कि जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई अन्य देश परमाणु हथियार बनाना शुरू कर सकते हैं। और, आप जानते हैं, वे पहले से ही इस बारे में बात कर रहे हैं। और इन देशों में परमाणु हथियारों को लेकर बहुत कुछ है - कुछ साल पहले तक जितना सोचा भी नहीं जा सकता था, उससे कहीं ज़्यादा। तो मैं आखिरी समस्या के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ जो शायद सामने आ सकती है, और वह है गोल्डन डोम की बात पर वापस जाना। लेकिन परमाणु निवारण के खतरों में से एक यह है कि कोई मिसाइल रक्षा प्रणाली लेकर आ सकता है, क्योंकि मिसाइल रक्षा प्रणाली किसी भी प्रकार की निवारण प्रणाली को मूल रूप से कमज़ोर कर देगी। हमें नहीं पता। जैसा कि मैंने कहा, मुझे संदेह है कि कोई मिसाइल रक्षा प्रणाली, विशेष रूप से बड़े देशों के लिए - सुरक्षा हेतु ठीक है - आपके पास मिसाइल रक्षा प्रणाली हो सकती है जो इज़राइल जैसे छोटे क्षेत्रों की रक्षा कर सके, शायद ताइवान भी, या जापान थोड़ा बड़ा है, लेकिन फिर भी। लेकिन चीन, भारत, अमेरिका, रूस जैसे बड़े देशों को मिसाइल से सुरक्षित करना आसान नहीं है। कवरेज बहुत अधिक है। लेकिन फिर, तकनीक बदलती है। हम अभी एक लेज़र-आधारित रक्षा प्रणाली की शुरुआत देख रहे हैं जिसे इज़राइल विकसित कर रहा है, और इसलिए कौन जानता है कि तकनीक कहाँ तक जाए। लेकिन यह वास्तव में खतरे का संकेत होगा, मुझे लगता है, अगले कुछ दशकों में अगर कोई मिसाइल रक्षा प्रणाली बड़े देशों के लिए बनाना संभव हो जाती है, तो निवारण, जैसा कि हम जानते हैं, खत्म हो जाएगा। और फिर यह काफी बुरा होगा। शायद मुझे अपनी बात यहीं खत्म करनी चाहिए। धन्यवाद, महोदय।

राजीव नयन: धन्यवाद। महोदय। और मैं राजदूत नूतन कपूर महावर को धन्यवाद देना चाहूँगा। मुझे लगता है कि मैं उनसे लगभग 20 साल बाद मिल रहा हूँ, जब वह डीआईएसए में थीं। उस समय मुझे सामूहिक विनाश के हथियार अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई थी, और वह प्रभारी थीं। इसलिए मुझे आमंत्रित करने हेतु आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं उनकी टीम, डॉ. निवेदिता रे, डॉ. संजीव कुमार और डॉ. मुकेश कुमार का भी आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। राजदूत कपूर ने जो सवाल उठाया, क्या यह व्यवस्था, परमाणु व्यवस्था, परिवर्तनशील है? मेरा मानना है कि हाँ, यह हमेशा से परिवर्तनशील रही है। पहले इस पर केवल संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभुत्व था, सब ठीक था, फिर सोवियत संघ आया, फिर अन्य यूरोपीय देश आए, और फिर चीन। जब चीन आया, तो अचानक दुनिया परमाणु व्यवस्था के बारे में बात करने लगी जो बहुपक्षीय से बहुध्रुवीय हो गई है। उस समय ध्रुव शब्द का प्रयोग किया जाता था। यह ध्रुवीकरण, शुरू हो गया है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वह ध्रुव, वह देश जिसने बहुध्रुवीय परमाणु व्यवस्था बनाई थी, अंततः दूसरे ध्रुव, यानी पश्चिमी दुनिया, में शामिल हो गया या उसके साथ चलने लगा। तो यह बहुत ही जटिल, जटिल परमाणु विश्व व्यवस्था है जिसका हम अभी साक्षी बन रहे हैं। उसके बाद, कई देश इसमें शामिल हुए। इज़राइल, किस तरह से यह मत पूछिए, और यह बताएगा भी नहीं। तो यह बहुत ही अजीब स्थिति है। इसलिए यह खुलासा नहीं करता, इसने परीक्षण नहीं किया। फिर हम दोनों इसमें शामिल हुए, और फिर उत्तर कोरिया संधि से हटने के बाद एक अनोखे तरीके से शामिल हुआ। तो यह हमेशा से थोड़ा गतिशील रहा है। परमाणु विश्व व्यवस्था गतिशील रही है, और देश, हथियार, सिद्धांत,

सभी इस गतिशीलता में योगदान देते रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि परमाणु विश्व की गतिशील व्यवस्था। तो वर्तमान स्थिति क्या है? क्या यह बुरा है, अच्छा है, बदसूरत है? यही वह सवाल है जो हमें पूछना चाहिए। मेरा कहना है, यह एक यथास्थिति है। यह न तो अच्छा है, न बुरा है, न ही बदसूरत है। यह रूढ़िवादी है। और यह हमेशा से अस्तित्व में रहा है। तमाम उकसावों के बावजूद, यह यथास्थितिवादी परमाणु विश्व व्यवस्था है। किस तरह के उकसावे? देखने को मिल रहे हैं और फिर मैं कहता हूँ, आप इसपर बहस कर सकते हैं। नई सैन्य संरचना, आधुनिकीकरण हो रहा है। तो यह एक और तरीका है। क्या यह प्रभावित कर रहा है? मुझे नहीं लगता। यह अभी भी मौजूदा निवारक संरचना में योगदान दे रहा है। तो यह बस खुद को नया रूप दे रहा है। क्या यह कुछ नया है? मेरा तर्क है, नहीं। शीत युद्ध के दौरान भी, हथियारों पर नियंत्रण ने मूल रूप से निवारक संरचना को मजबूत किया था। अनावश्यक हथियार इस दौड़ से बाहर हो गए थे। और नई प्रणाली, नई हथियार प्रणालियाँ, मौजूदा निवारक संरचना को मजबूत करती हैं। तो यह वास्तविकता है। तो अगर हम हैं भी, तो कई लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, अब वे वारहेड्स का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, नए हाइपरसोनिक हथियार, सुपरसोनिक हथियार, सबसोनिक हथियार आ रहे हैं, वे संरचना को प्रभावित करेंगे। मेरा तर्क है कि शीत युद्ध के दौरान भी हथियार संरचना, वितरण वाहनों को बेहतर किया जा रहा था। लेकिन किसी न किसी तरह सभी को इस बात का महत्व समझ में आ गया है कि इसे कैसे बनाए रखा जाए, यह एक व्यक्तिपरक शब्द है, लेकिन यह बहुत कुछ सामने लाता है, यानी रणनीतिक स्थिरता। इसे कैसे परिभाषित किया जाए? क्या इसकी कोई सटीक परिभाषा है? जवाब है, नहीं। आरएएनडी ने एक अध्ययन किया था। और उसने प्रणाली को स्थिर या अस्थिर, परमाणु व्यवस्था का आकलन करने हेतु लगभग 11, 12 पैरामीटर तय किए थे। और उनमें से कई में गड़बड़ी हुई, फिर भी प्रणाली स्थिर रही। फिर भी हमें प्रणाली में कोई गड़बड़ी नहीं मिली। तो यही हकीकत है।

अभी राजेश ने नई तकनीकों के आने की बात की और जब मुझे पत्र मिला, तो उसमें यह भी लिखा था कि क्या ये नई उभरती हुई तकनीकें सामरिक स्थिरता, विश्व व्यवस्था, परमाणु प्रवाह को प्रभावित कर रही हैं, क्या इन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है? फिर से मेरा कहना है कि, मुझे इसकी परवाह नहीं है। क्या हो रहा है? सबसे पहले, इस उन्नत तकनीक, नई तकनीक को परिभाषित करना बहुत मुश्किल है। जैसा कि मैंने बताया, हथियारों का आधुनिकीकरण किया जाता है, उन्हें बेहतर किया जाता है और पुरानी प्रणालियों को छोड़ दिया जाता है। एक बार जब आपको लगता है कि यह उपयोगी नहीं है, तो आप इसे छोड़ देते हैं। आप इसे क्यों रखेंगे? तो अब क्या हो रहा है? अब छह, सात हथियार या तकनीकें हैं जिन्हें उभरती हुई कहा जा रहा है और जो परमाणु व्यवस्था या परमाणु प्रणालियों हेतु प्रासंगिक हो सकती हैं। तो वे क्या हैं? एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटिंग शक्ति। तो क्या यह बुरा है? मुझे लगता है कि यह आमतौर पर ऐसा सवाल है जो तुरंत उठता है और इस पर कई लेख आ चुके हैं। यह अपने लक्ष्य खुद चुनना शुरू कर देगा, मानो इसमें से मानवीय तत्व गायब हो रहे हों। मानवीय तत्व तो होंगे ही। इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। इसलिए इसमें सुधार होगा। वास्तव में, यदि आप इसका सही उपयोग करते हैं, तो यह आपके निवारण ढांचे में मदद करेगा। यह ऐसा बिंदु है जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा। फिर सवाल आता है, सेंसर, परिशुद्धता, यह प्रणाली की परिशुद्धता को बढ़ाएगा। प्रणाली की परिशुद्धता क्या है? क्या यह परमाणु हथियार गिराने हेतु बहुत प्रासंगिक है? सभी मिसाइलों,

आम तौर पर सभी में बहुत अधिक सर्कुलर त्रुटि की संभावना होती है। सभी में सुधार हो रहा है, 0.01, 0.02, 0.03, यहां तक कि 0.05 भी आप मान लें, इससे क्या फर्क पड़ता है? यह पारंपरिक हथियारों के लिए मायने रख सकता है लेकिन परमाणु हमला होने पर परमाणु हथियारों के लिए यह मायने नहीं रखेगा। तीसरा है गति, हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक बीएमडी प्रणाली को पीछे छोड़ देगा और फिर आप किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करेंगे और निवारण बस ध्वस्त हो जाएगा। यह फिर से एक अन्य बेतुका तर्क है जो मुझे लगता है कि दुनिया भर में जिसे रखा जा रहा है। गति, वैसे भी गति होती है। एक बार जब आप इरादा करना चाहते हैं, जैसा कि राजेश ने सही कहा, रेथियॉन जैसी कई कंपनियां, रक्षा कंपनियां भी 92% प्रभावशीलता का दावा करती हैं, सबसे बेहतरीन। तो फिर से 8% भेद्यता बहुत अधिक है। तो यह तो है ही। तो फिर, यहाँ भी मुझे ऐसा नहीं लगता। दरअसल, मेरा तर्क यही रहा है कि अगर आप इसका सही इस्तेमाल करें, तो बेहतर सत्यापन संरचना हो सकती है, आप अपने सभी समझौतों का सत्यापन कर सकते हैं, आपकी कमान एवं नियंत्रण संरचना बेहतर होगी, और आपके पास बेहतर जानकारी होगी, सूचनाओं का बेहतर आदान-प्रदान होगा। कई बार, मान लीजिए, जब कोई ग़लतफ़हमी या गलत जानकारी आ रही हो, तो आप अंतरिक्ष से इस तकनीक के ज़रिए उसकी पुष्टि कर सकते हैं। आप यह तय कर सकते हैं कि ठीक है, वहाँ ऐसा हो रहा है, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है, या अगर कोई चिंता की बात है, और अगर मुझे कोई पूर्व-आक्रमण करना पड़े, तो मैं वह करूँगा। तो यह बात तो है ही। इसलिए मुझे लगता है कि ये सभी तकनीकें काफी मददगार हैं, और मुझे लगता है कि हमें इसके लिए काम करना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या यह अभी भी विश्वसनीय है? मुझे लगता है कि कुल मिलाकर, यह विश्वसनीय है। तो कुल मिलाकर, यह विश्वसनीय है। भविष्य क्या होगा? मुझे लगता है कि मैं सीधे उसी पर आता हूँ। भविष्य एक यथास्थिति है। कुछ खास बदलने वाला नहीं है। ओबामा को नोबेल पुरस्कार मिला और वह खुश हैं। इसके बाद, ट्रम्प अलग कारणों से इसकी मांग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मुझे ट्रम्प में उम्मीद दिखाई देती है। वह एक सनकी व्यक्ति हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए वह - और अगर वह परमाणु हथियारों की लागत की गणना करते हैं, तो मुझे लगता है कि वह परमाणु निरस्त्रीकरण की ओर जाएंगे। अगर आप इसे कहीं भी इस्तेमाल नहीं करने करने वाले हैं तो आप परमाणु हथियारों का क्या करने वाले हैं? आप क्या करेंगे? मुझे लगता है कि अगर - हमने गणना की है और बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट्स ने प्रति मिनट लागत की गणना की है - परमाणु हथियारों की प्रति मिनट लागत। अगर वह वास्तव में - यह रिपोर्ट उन्हें दिखाई जाती है, तो मुझे लगता है कि वह कुछ अच्छा कर सकते हैं। वह जो कर रहे हैं - यह तर्कसंगतता की अतार्किकता है चीन - सब कुछ चीन पर निर्भर करता है कि चीन एक शक्ति के रूप में कैसे उभर रहा है। अगर इसमें कमी आती है, तो विश्व व्यवस्था में, मान लीजिए, गतिशीलता, परिवर्तन हो सकते हैं। हम अलग तरीके का परिवर्तन देखेंगे और हम खुश होंगे। एनपीटी मुख्य बनी रहेगी - परमाणु व्यवस्था का मुख्य इतिहास, चाहे आप इसे पसंद करें या नहीं। ये सभी देश, सदस्य देश, बस शोर मचाते हैं। कोई भी इस संधि से बाहर नहीं आया। सभी इस स्थिर परमाणु व्यवस्था से खुश हैं। मैंने नहीं देखा। सभी शोर मचाते हैं। क्या आपको रेवकॉन के बाद कोई एनपीटी सदस्य देश एनपीटी से बाहर आता हुआ दिखाई दिया? नहीं, वे खुश हैं। यहाँ तक कि नॉन-एनपीटी देश भी खुश हैं। वे बस प्रेपकॉन, रेवकॉन के दौरान सामान्य नियमित शोर मचाते हैं, इसलिए हम रेवकॉन के दौरान मिस्र और अन्य देशों द्वारा की गई कुछ शोरगुल देखते रहेंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो यही होने वाला है। इसलिए हमें बस व्यवस्था

को संभालना है। और भारत, मैंने भारत के बारे में बात नहीं की। जब आप प्रश्न पूछेंगे, तो मैं भारत और पाकिस्तान के बारे में बात करूँगा। मैं इस पर और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, उस पर नज़र रख रहा हूँ। मैं इस बारे में बताऊँगा कि कैसे बदलाव आए हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद, महोदय।

रेशमी काज़ी: धन्यवाद, सर। बहुत-बहुत धन्यवाद, सर। धन्यवाद, आईसीडब्ल्यूए। धन्यवाद, श्रीमती महावर, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आप सभी का धन्यवाद। हम इस तरह की दोपहर में परमाणु मुद्दों पर बात कर रहे हैं। और इस विषय पर अंतिम वक्ता होना मेरे लिए एक तरह से सौभाग्य की बात है क्योंकि कहने को ज़्यादा कुछ नहीं है। मेरे को-पैनलिस्ट बहुत ही अच्छे हैं। और जैसा कि उन्होंने कहा, परमाणु, हम वहाँ थे। उन्होंने इस पर बहुत अच्छी चर्चा की है। डॉ. नयन मेरे समन्वयक थे, इसलिए मैंने उनके अधीन काम किया। और राजेश हमेशा से मेरे पसंदीदा रहे हैं। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने कहा, अंतिम वक्ता होने के नाते, कहने को ज़्यादा कुछ नहीं है, इसलिए मैं यहाँ बहुत ही व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने वाली हूँ। परमाणु प्रवाह या न्यूक्लियर फ्लक्स की बात करें तो, बहुत से लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो न्यूक्लियर फ्लक्स क्या है**?** मूल रूप से, यह वैश्विक परमाणु परिदृश्य में एक तेज़, अव्यवस्थित बदलाव को दर्शाता है। हमारे पास आँकड़े हैं। हमारे पास सिद्धांत हैं। हमारे पास तकनीकें हैं। मेरे को-पैनलिस्टों ने इसके बारे में बात की। हमारी संधियाँ और राजनीतिक जुड़ाव हैं। और सब कुछ बहुत ज़्यादा अस्थिर लग रहा है। तो ये सब परमाणु राजनीति को कुछ साल पहले की तुलना में कम स्थिर और कम पूर्वानुमानित बना रहा है। तो क्या बदल रहा है**?** इसके पीछे क्या कारण हैं**?** जैसा कि मैंने कहा, यह एक सामान्य नज़रिया है। तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ, शस्त्रागार बदल रहे हैं। कुछ देश तेज़ी से इसे बढ़ा रहे हैं। कुछ अपने परमाणु बलों का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, चीन उनमें से एक है। इसने इनके निर्माण में तेज़ी ला दी है। फिर हमारे पास सिद्धांत और बयानबाज़ी है। ये भी बदल रहा है। परमाणु-सशस्त्र देश इस बात को समायोजित कर रहे हैं कि वे कब और कैसे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो हमारे पास ऐसा परमाणु-सशस्त्र देश है जो रूस और यूक्रेन जैसे गैर-परमाणु-सशस्त्र देश पर हमला कर रहा है, यह संकट अभी भी जारी है। फिर आपके पास दो परमाणु-सशस्त्र देश हैं। इज़राइल ने अभी तक घोषणा नहीं की है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि उसके पास एडवांस परमाणु क्षमता है। तो ऐसे दो परमाणु-सशस्त्र देश हैं जो एक गैर-परमाणु-सशस्त्र देश या शायद सीमांत परमाणु-सशस्त्र देश, यानी ईरान पर हमला कर रहे हैं। अमेरिका और इज़राइल ईरान पर हमला कर रहे हैं। फिर हमारे पास हथियार नियंत्रण ढाँचा है। फिर से, वे मुक्त हो रहे हैं। आपके पास प्रमुख संधियाँ, वैधता की आदतें हैं, जो दबाव में हैं। नई शुरुआत के भविष्य को लेकर हम आशावादी हैं, लेकिन अब जबकि रूस ने इस बारे में कुछ उम्मीद दिखाई है, हम ट्रम्प को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं हैं, इसलिए यह फिर से एक बड़ी चिंता का विषय है। हमारे पास नई सैन्य तकनीकें हैं जो स्थिरता को मुश्किल बना रही हैं। आपके पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, मिसाइल रक्षा प्रणालियों में प्रगति है, साइबर ऑपरेशन चेतावनी देना और फिर से निर्णय लेना काफी कठिन बना देते हैं। इसके साथ ही, हमारे सामने प्रसार का दबाव एवं क्षेत्रीय संकट भी है, इसलिए ईरान को लेकर तनाव है, डीपीआरके के चल रहे घटनाक्रम को लेकर तनाव है। ये क्षेत्रीय जोखिम और कूटनीतिक

संघर्ष भी बढ़ाते हैं। तो इसने वैश्विक राजनीति पर जो प्रभाव डाला है, वह फिर से एक बहुत ही सामान्य दृष्टिकोण है। संकट की अस्थिरता अधिक है, तेज़ हथियार, अस्थिर कमान व नियंत्रण, अस्पष्ट सिद्धांत, ये सब इस खतरे को बढ़ाते हैं कि संकट कभी-कभी अनजाने में बढ़ जाता है। अधिक दबाव है, अधिक अस्पष्टता है, देश धमकियों का उपयोग करते हैं, परमाणु खतरों को राजनीतिक लाभ के रूप में, निवारक बल प्रयोग की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे सामने क्षेत्रीय हथियारों की दौड़ भी है, फिर हथियार नियंत्रण संस्थानों का प्रभाव कम हो रहा है, संधियों और सत्यापन के बिना बहुत अधिक अस्पष्टता बढ़ रही है, पारदर्शिता है, पारदर्शिता का अभाव है, जिससे कूटनीति काफी कठिन हो रही है। और फिर गठबंधन और विस्तारित निवारक, इसका भी परीक्षण हो रहा है। इसलिए अमेरिकी सहयोगियों और अन्य भागीदारों को परमाणु छत्रों और पारंपरिक बलों पर निर्भरता पर फिर से विचार करना चाहिए। कुछ ठोस उदाहरण अमेरिकी और स्वतंत्र विश्लेषकों का कहना है कि चीन के वारहेड भंडार में काफी वृद्धि हुई है। अनुमान है कि **2035** तक यह कई सौ वारहेड को पार कर जाएगा, जैसा कि आंकड़े बताते हैं **1,000** तक। रूस ने पहले ही सैद्धांतिक परिवर्तनों का संकेत दिया है और यूक्रेन के संदर्भ में वृद्धि के लेकर पश्चिमी चिंता बढ़ने के साथ अधिक परमाणु संकेत का उपयोग किया है। नई एसटीएआरटी संधि अमेरिका-रूस के बीच हथियार नियंत्रण का अंतिम प्रमुख आधार है, लेकिन इसमें बहुत अधिक अनिश्चितता है, और यह अस्थिरता का एक प्रमुख कारक है। हाइपरसोनिक और अन्य नई वितरण प्रणालियाँ उभर रही हैं, जो पता लगाने और प्रतिक्रिया देने की समयसीमा को जटिल बना रही हैं, जिससे संकट में निर्णय लेने का समय कम हो रहा है। ईरान अभी भी टकराव का केंद्र बना हुआ है, कूटनीतिक मतभेद और आईएईए की चिंताएँ मध्य पूर्व को प्रसार का एक संभावित केंद्र बना रही हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या है**?** न्यूक्लियर फ्लक्स का अर्थ है कि परमाणु व्यवस्था गतिमान है। कहीं ज़्यादा हथियार, कमज़ोर हथियार नियंत्रण ढाँचा, बदलते सिद्धांत और विघटनकारी तकनीकें। अगर आप डेविड ईस्टन के इनपुट-आउटपुट मॉडल का इस्तेमाल करें, तो कुछ माँगें हैं, कुछ माँगें जो इस ढाँचे पर थोपी जा रही हैं, चाहे वे संधियों के रूप में हों, चाहे ज़्यादा से ज़्यादा नए देशों के रूप में हों या परमाणु क्षमता की चाह रखने वाले छिपे देशों के रूप में। तो ये माँगें मौजूद हैं। क्या इन माँगों को समर्थन मिल रहा है**?** क्या इन माँगों को वह समर्थन मिल रहा है जो उन्हें मिलना चाहिए**?** नहीं। तो नतीजा क्या है**?** इसमें ग़लत अनुमान लगाने की संभावना, कूटनीति को और कठिन बनाना, स्थिरता एवं पूर्वानुमान का संयोजन है। काफ़ी अनिश्चितता है। ये सभी बातें देशों और गठबंधनों को तेज़ी से बदलाव करने हेतु मजबूर कर रही हैं। तो कुल मिलाकर, शीत युद्ध और शीत युद्ध के बाद की परमाणु स्थिरता का आधार रही पूर्वानुमानशीलता धीरे-धीरे कम हो रही है, और भू-राजनीति को इसके साथ तालमेल बिठाने की ज़रूरत है। तो आख़िर वैश्विक परमाणु स्थिरता का आधार क्या था और ये किस तरह बदल रहे हैं**?** वैश्विक स्थिरता का आधार क्या था, मैंने यहाँ एक सूची बनाई है, तो पहला स्तंभ, पारस्परिक भेद्यता, बनी रहने योग्य दूसरी हमलावर शक्तियाँ। यह क्यों महत्वपूर्ण था**?** क्योंकि मेरी क्षमता आपके पहले हमले को बेअसर कर सकती है। और अगर आपका पहला हमला बेअसर हो जाता है, तो यह इस तर्क पर आधारित है कि पारस्परिक रूप से सुनिश्चित विनाश हेतु प्रत्येक प्रमुख शक्ति के पास मज़बूत और बचे रहने योग्य शक्ति थी, जिनमें आईसीबीएम, पनडुब्बी, और मज़बूत साइलो शामिल थे। इसलिए कोई भी यह उम्मीद नहीं कर सकता था कि निरस्त्रीकरण का पहला हमला दूसरे पक्ष की जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता को खत्म कर देगा। क्या हम अभी भी ऐसा ही कर रहे हैं**?** देश आधुनिकीकरण कर रहे हैं, वे

वितरण प्रणालियों में विविधता ला रहे हैं, और कुछ फिर से बहुत बड़े शस्त्रागार का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए समानता और यह गणना कि कौन पहले हमले को झेल सकता है, कम स्थिर और कम अनिश्चित हो रही है। चीन का तेज़ी से साइलो का सृजन और भंडार वृद्धि इसका एक स्पष्ट उदाहरण है। स्तंभ संख्या औपचारिक हथियार नियंत्रण संधि, एक समय पहले, यानी शीत युद्ध से पहले, या यूँ कहें कि शीत युद्ध के दौर में, उनके सत्यापन की पारदर्शिता। संधियों, सीमित संख्या में सैनिकों की तैनाती, सत्यापन उपकरणों की स्थापना, इसने पूर्वानुमानित नियम बनाए। यह कैसे बदल रहा है? प्रमुख समझौते कमज़ोर हो गए हैं या खत्म कर दिए गए हैं। नई शुरुआत में, अभी भी बहुत अनिश्चितता है, जैसा कि वहाँ दिखाई दे रहा है। इसलिए संधि-आधारित सत्यापन में कमी से अस्पष्टता और हथियारों की दौड़ को बढ़ावा मिलता है। स्तंभ संख्या तीन, स्थिर सिद्धांत एवं संयमित संकेत। ये पूर्वानुमानित सीमा रेखाएँ हैं। और ये कुछ समय पहले भी मौजूद थीं। यह कैसे बदल रहा है? कुछ देशों की सीमाएँ धुंधली हो गई हैं या वे दबावपूर्ण परमाणु बयानबाजी कर रहे हैं। इसलिए, तनाव बढ़ाने वाली भाषा ज़्यादा स्पष्ट है, खासकर जैसा कि हमने रूस-यूक्रेन संकट के समय देखा। यह अस्पष्टता संकट की अस्थिरता को बढ़ाती है क्योंकि विरोधी यह तय नहीं कर सकते कि कौन सी कार्रवाई परमाणु प्रतिक्रियाओं को गति देगी। स्तंभ संख्या चार, एक विश्वसनीय विस्तारित निवारण और गठबंधन संरचना। यह मायने रखता था। क्यों? क्योंकि अमेरिकी परमाणु की छत्रछाया ने सहयोगी देशों को स्वतंत्र परमाणु शक्ति विकसित करने से रोका और क्षेत्रीय संतुलन को स्थिर किया। लेकिन अब यह बदल रहा है। कैसे? हमें गठबंधन की प्रतिबद्धताओं को लेकर कोई संदेह नहीं है। हमने अभी देखा कि कतर के अल-उदीद अड्डे पर क्या हुआ, और उसने फिर से, बहुत सारी आशंकाएँ, बहुत सारे संदेह पैदा किए हैं। स्तंभ संख्या पाँच, अंतर्राष्ट्रीय मानदंड, अप्रसार व्यवस्थाएँ और संस्थान। यह मायने रखता था। एनपीटी, आईएईए, निर्यात नियंत्रण, राजनीतिक कलंक, परमाणु वर्जनाएँ। इसने प्रसार हेतु बहुत सारी कूटनीतिक और भौतिक लागतें बढ़ाईं, इसने गुप्त कार्यक्रमों का पता लगाने में मदद की, विवाद समाधान हेतु आउटलेट प्रदान किए, लेकिन यह फिर से बदल रहा है। कूटनीति में तनाव, कुछ वर्षों में एनपीटी समीक्षा सम्मेलनों में गतिरोध, आईएईए पहुँच, सत्यापन चुनौतियाँ, क्षेत्रीय संकट, चाहे ईरान हो, उत्तर कोरिया हो, वे परमाणु अप्रसार ढाँचे पर ज़ोर दे रहे हैं और इस विश्वास को कम कर रहे हैं कि नियम एवं निरीक्षण प्रसार जोखिमों को मज़बूती से रोक या हल कर सकते हैं। इसलिए इसमें थोड़ी एन्ट्रॉपी है, परमाणु एन्ट्रॉपी। स्तंभ संख्या छह, स्थिर संकट प्रबंधन पद्धतियाँ और परमाणु जोखिम न्यूनीकरण उपाय। ये बहुत मायने रखते थे। हॉटलाइन, समुद्री दुर्घटना समझौते, संलग्नता के नियम, सैन्य-से-सैन्य संचार की आदत, दुर्घटनाओं की संभावना कम करना, गलत तरीके से युद्धाभ्यास, साइबरस्पेस घटनाएँ परमाणु संकट में बदल जाती हैं। यह फिर से बदल रहा है। कैसे? सैन्य प्रतिस्पर्धा, नियमित आदान-प्रदान का निलंबन, हमले के नए तरीके, साइबरस्पेस। उन्होंने नियमित संपर्क की पुरानी परंपरा को कमज़ोर कर दिया है और किसी घटना को गलत तरीके से समझे जाने की संभावना बढ़ा दी है। इस प्रकार निर्णय का समय कम हो रहा है और ऐसी स्थिति के बढ़ने का जोखिम बढ़ रहा है। और इसके अलावा, हमारे पास बहुत सारे तकनीकी और परिचालन चालक हैं जो इन सभी स्तंभों में काम कर रहे हैं। मैं यहीं अपनी बात खत्म करती हूँ। थ्रेसहोल्ड के लेकर अधिक अनिश्चितता, उच्च अस्थिरता, उच्च संकट अस्थिरता, हेजिंग व हथियारों की होड़ को प्रोत्साहन, और जैसा कि मैंने कहा, परमाणु एन्ट्रॉपी। बस एक छोटा सा बिंदु है। विलंबता को लेकर बहुत चर्चा होती है। तो विलंबता का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि आप अपनी परमाणु

क्षमता की सीमा या उसके कुछ हिस्से पर हैं। अब, यह फिर से एक समस्या है। आप कह सकते हैं कि, ठीक है, विलंबता का अर्थ यह नहीं है कि आपने अपनी परमाणु क्षमता हासिल कर ली है, लेकिन इसके दो त्वरित बिंदु हैं। दो त्वरित बिंदु हैं। यह ब्रेकआउट समय को कम करता है और यह सिग्नलिंग व हेजिंग को बदलता है। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

राकेश सूद: धन्यवाद। और अब मंच सवालों के लिए खुला है। हाँ, कृपया। क्या हम यहाँ माइक्रोफ़ोन ले सकते हैं? हम एक साथ तीन सवाल लेंगे।

कामेल गलाल: मैं बहुत जल्दी अपनी बात पूरी करूंगा। मैं बहुत कम समय में अपनी बात रखूँगा। मेरा नाम कामेल गलाल है। मैं मिस्र का राजदूत हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। यह एक बहुत ही ज्ञानवर्धक सत्र रहा। आप जानते हैं, राजनयिकों के पास जब माइक्रोफ़ोन होता है, तो वे कई दिनों तक बोल सकते हैं। इसलिए मैं सीधी बात रहूँगा। सबसे पहले, परमाणु प्रणाली। जैसा कि राजदूत ने कहा, हम मिस्र में इतने सालों से वो लोग बन गए हैं जिनके पास कुछ नहीं है। और इसके पीछे एक कारण है। और मैं इस मुद्दे पर मिस्र की आवाज़ के बारे में आपकी टिप्पणी का उत्तर देते हुए, श्री राजीव, इसी कारण पर वापस आऊँगा। तो परमाणु प्रणाली दो घटकों पर केंद्रित है, एनपीटी, अनुच्छेद 4 एवं अनुच्छेद 6। सभी इसके बारे में जानते हैं, अप्रसार और निरस्त्रीकरण। मैं इस विषय का विशेषज्ञ नहीं हूँ। लेकिन हम हमेशा परमाणु अप्रसार पर ध्यान केंद्रित करते हैं जबकि बाकी सभी, जैसे मेरा देश, निरस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। क्योंकि तथ्यों से यह साबित हो चुका है कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से निवारण होना अप्रभावी है। और हाल ही में घटित सभी उदाहरण इसे साबित करते हैं। ईरान में जो हुआ वह इसे साबित करता है। इज़राइल में जो हुआ वह इसे साबित करता है। और यहाँ जो हुआ वह इसे साबित करता है। इसलिए परमाणु हथियार होने से वास्तव में कोई नहीं रुकता। मेरा देश 1973 में एक दिन इज़राइल के साथ युद्ध में उतरा था जबकि उनके पास परमाणु हथियार थे। यह किसी को भी अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने या उनकी रक्षा करने से नहीं रोकता। तो यह बात पक्की है। श्री राजीव, मैं आपको बस इतना बता दूँ कि हाँ, हम रुकेंगे। यह सच है कि जैसा कि आपने बताया, जब परमाणु हथियारों की बात आती है तो मिस्र आमतौर पर बहुत शोर मचाता है। मिस्र द्वारा आमतौर पर मचाए जाने वाले इस शोर के कारण का उत्तर देने के लिए, जो कि सच है, हम पिछले 7,000 वर्षों से ऐसा कर रहे हैं। हमें अपने इतिहास और दुनिया के इतिहास से सीखने की आदत है। और हमने सीखा है कि हथियार किसी को सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा। और यह पूरे इतिहास में सिद्ध हो चुका है। साम्राज्य बने और गिरे। एक दिन परमाणु हथियार कुछ देशों का समुद्री साम्राज्य बन गए। और यह साम्राज्य धीरे-धीरे लुप्त हो गया। और लोग और सिद्धांत ही बचे रहे। तो आपके सवालों का उत्तर देते हुए, हमारी विदेश नीति, और इसीलिए हम परमाणु हथियारों के बारे में इतना शोर मचाते हैं, हमारी विदेश नीति चार 'पी' पर आधारित है। पीस (शांति), प्रूडेंस (विवेक), और इस तरह के मुद्दे से निपटने में यही मुख्य तत्व है। और पार्टनरशिप (साझेदारी) व पर्सीवरेंस (दृढ़ता)। इसलिए यही कारण है कि जब परमाणु हथियार, जो हत्या का एक साधन है, के बारे में बात करने की बात आती है, तो हम बहुत शोर मचाते हैं। यह नहीं रुकेगा, यह किसी हेतु निवारण नहीं बनेगा, यह नहीं बना, और यह नहीं बनेगा। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

राकेश सूद: मुझे लगता है कि यह बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़बरदस्त बात है। हाँ, ठीक है।

आर्टेम नोस्को: मेरा नाम आर्टेम नोस्को है। मैं यूक्रेन दूतावास से हूँ। इस बेहत स्पष्ट परिचय और आपकी अंतर्दृष्टि के लिए धन्यवाद। तो सबसे पहले, मैं परमाणु अप्रसार और निवारण के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। सोवियत संघ के पतन के बाद, यूक्रेन को तीसरा सबसे बड़ा परमाणु शस्त्रागार हासिल हुआ, अमेरिका और रूस के बाद दूसरा, यानी यह चीन से भी बड़ा था, यह फ्रांस और किसी भी अन्य देश से बड़ा था। सुरक्षा की गारंटी के बदले में, हमने इस परमाणु शस्त्रागार को त्याग दिया। हमारे पास न केवल हथियार थे, बल्कि उन्हें पहुँचाने की क्षमता भी थी, जो और भी महत्वपूर्ण बात है। इसलिए हमने सुरक्षा की गारंटी के बदले में उन्हें नष्ट कर दिया। लेकिन रूस, एक परमाणु देश और सुरक्षा का गारंटर होने के बावजूद, आक्रमण कर गया। और वास्तव में, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के नज़रिए से, यह कोई संकट नहीं, बल्कि आक्रमण है। तो चलिए, कूटनीतिक और राजनीतिक होने के बावजूद, सच को सच कहते हैं, लेकिन कानूनी नज़रिए से यह सच है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या आप मानते हैं कि जो कुछ हुआ और रूस ने परमाणु सुरक्षा के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को एक बड़ा झटका दिया, क्योंकि सभी जानते हैं कि यह सिर्फ़ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल न करने की बात नहीं है, बल्कि इन परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी का भी मामला है। तो क्या आप अब भी मानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय महत्वाकांक्षी देशों को किसी भी तरह की सुरक्षा की गारंटी के बदले में अपनी आकांक्षाओं को त्यागने हेतु मना सकता है, बिना किसी ठोस और वास्तविक गारंटी के, सिर्फ़ शब्दों के नहीं? और दूसरी बात, परमाणु विस्फोट की स्थिति में, यह दुनिया के किसी भी देश को प्रभावित करेगा। और क्या आपको लगता है कि किसी भी संघर्ष में, जब परमाणु हथियारों का सवाल हो और धमकी का इस्तेमाल अभी भी तटस्थ रहे, किसी तीसरे देश के लिए यह उचित और न्यायसंगत है? बस इंतज़ार करना, अपनी चिंता व्यक्त न करना और सिर्फ़ परमाणु हथियारों से बचने हेतु हस्तक्षेप करना न सिर्फ़ निवारण बन जाता है, बल्कि काइनेटिक युद्ध का एक हिस्सा बन जाता है, क्योंकि यह एक बहुत ही गंभीर खतरा है। तो यह बहुत स्पष्ट हो सकता है।

राकेश सूद: धन्यवाद। यहाँ दो ऐसे देश हैं जो परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) के पक्षकार हैं और परमाणु निवारण की उपयोगिता या उसके न होने के बारे में उनकी राय बहुत अलग है। तो शायद हम ऐसा कर सकते हैं, आप एक द्विपक्षीय समझौता कर सकते हैं, मुझे लगता है कि यह एक बुनियादी सवाल है, हाँ।

विजय नायक: मेरा नाम विजय नायक है। मैं एक पत्रकार हूँ। पिछले हफ़्ते हमने पाकिस्तान को यह कहते सुना कि वे सऊदी अरब को परमाणु तकनीक दे सकते हैं। मैं बस इस घटनाक्रम पर पैनलिस्टों की राय जानना चाहता हूँ, क्या इससे सऊदी अरब और इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंधों में समस्याएँ पैदा होंगी।

सुश्री पिल्लई: सभी सम्मानित पैनलिस्टों को नमस्कार। इस तरह के ज्ञानवर्धक व्याख्यान को सुनने हेतु यहाँ उपस्थित होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो सीधे अपने सवाल पर आते हैं, क्या ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देशों द्वारा परमाणु हथियारों की खोज परमाणु अप्रसार व्यवस्था की विफलता का परिणाम है, या यह महाशक्ति की सुरक्षा की गारंटी में आई कमी के प्रति उनकी तर्कसंगत प्रतिक्रिया है? धन्यवाद।

अज्ञात वक्ता: नमस्कार। मेरा सवाल पैनल में उपस्थित सभी लोगों से है। परमाणु प्रवाह यानी न्यूक्लियर फ्लक्स पर इस चर्चा का स्वरूप क्या है? क्या अब हम यह मान रहे हैं कि परमाणु हथियार महँगे और मात्र सजावट के हथियार हैं जिनका इस्तेमाल तब तक नहीं किया जाएगा जब तक एक सीमा पार न हो जाए, और बदले में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और हल्के व प्रभावी हथियारों का इस्तेमाल करेंगे? ये हथियार ज़्यादा सस्ते, ज़्यादा सघन और घातक होते हैं। धन्यवाद।

राकेश सूद: मुझे लगता है कि राजदूत द्वारा उठाए गए मुद्दे सही हैं, पहला यह कि परमाणु हथियार सुरक्षा प्रदान नहीं करते और न ही डराते हैं, और दूसरा यह कि अगर यूक्रेन ने 1994 के ज्ञापन के तहत उस समय अपने हथियार नहीं छोड़े होते, तो शायद यूक्रेन का भविष्य अलग होता, और रूस यूक्रेन पर हमला नहीं करता। तो हम इस बहस को छोड़ सकते हैं, लेकिन परमाणु हथियार सुरक्षा तो करते ही हैं।

कामेल गलाल: क्या इसने यूक्रेन को अपने साथ हो रही घटनाओं से खुद का बचाव करने से रोका? इसने उनका बचाव नहीं किया, क्योंकि रूस के पास परमाणु हथियार हैं।

राकेश सूद: हाँ, इसने रोका नहीं है, हाँ। इसने रोका नहीं है।

कामेल गलाल: तो परमाणु हथियारों का अस्तित्व अपने आप में उतना महत्वपूर्ण नहीं है।

राकेश सूद: लेकिन ऐसा हुआ, अगर उन्होंने किया होता, तो राजदूत जो कह रहे थे वह यह था कि अगर हमने उन्हें नहीं छोड़ा होता, तो क्या रूस ने छोड़ा होता?

आर्टेम नोस्को: दरअसल, मैंने सुरक्षा की गारंटी के बारे में पूछा था। ऐसा नहीं है कि हमें सुरक्षा की गारंटी मिलेगी, बल्कि मैंने सुरक्षा की गारंटी के बारे में पूछा था।

राकेश सूद: खैर, सुरक्षा की गारंटी, उसकी प्रासंगिकता, लेकिन मैं पैनलिस्टों के लिए मंच खोल देता हूँ, शायद हम आपसे शुरुआत कर सकते हैं, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें। लेकिन यह ज़रूरी नहीं है, मेरा मतलब है, आप पर है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो आप बहुत ही स्पष्ट और संक्षिप्त उत्तर दें। क्योंकि, हमारा समय पहले ही खत्म हो रहा है और मैं पीछे हटने से पहले कुछ और सवाल पूछना चाहूँगा।

रेशमी काज़ी: सुरक्षा की गारंटी के मुद्दे पर, इस समय बस इतना ही कहा जा सकता है कि परमाणु हथियार संपन्न देशों और परमाणु हथियार सीमा वाले देशों की ओर से और ज़्यादा ज़िम्मेदारी से काम करने की ज़रूरत है। ज़िम्मेदारी और ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत है। आपके सामने सुरक्षा के नकारात्मक आश्वासन जैसी कुछ चीजें भी हैं, जहां, आप जानते हैं, एनपीटी ने भी कहा है कि, जैसे, गैर-परमाणु हथियार देशों पर कोई हमला नहीं होना चाहिए।

राकेश सूद: हम उसमें नहीं पड़ रहे हैं। मैंने बाकी सवालों के बारे में कहा था।

रेशमी काज़ी: ठीक है। हाँ। तो, आप जानते हैं, इसमें ज़्यादा ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। और न्यूक्लियर फ्लक्स के मामले में, सीमा क्या है? सीमा, फिर से, इस लिहाज़ से कहना बहुत मुश्किल सवाल है, सीमा तय करना। क्योंकि कैसे, क्या मापदंड हैं? आप अपनी परमाणु क्षमता की श्रेष्ठता के संदर्भ में सीमा को कैसे मापेंगे? यह भी बहुत अस्पष्ट है। क्योंकि परमाणु श्रेष्ठता के संदर्भ में, अगर आप इसे मेगाटन भार या अपनी, आप जानते हैं, वितरण प्रणालियों के संदर्भ में मापेंगे, तो यह फिर से, यह बहुत अस्पष्ट है। यहाँ ज़रूरत सटीकता की है। अगर आप सीमा के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो वह कौन सा स्तर है जिस पर, आप जानते हैं, आप सीमा तक पहुँच सकते हैं? मुझे लगता है कि यह सटीकता, भेदन क्षमता, आपके लक्ष्य पर आप कितनी ज़ोर से प्रहार कर रहे हैं, के संदर्भ में है। और हाँ, आप जानते हैं, आपकी सैद्धांतिक स्थिति की तरह, चाहे आप इसे पहले हमले तक सीमित रखना चाहें या दूसरे हमले तक। दूसरे हमले का मतलब है, आप जानते हैं, जवाबी कार्रवाई, जवाबी कार्रवाई का दूसरा दौर, क्या वह पहले हमले को झेल पाएगा और फिर दूसरे हमले के साथ वापस आएगा। इसमें कई परतें होंगी, आप जानते हैं, इसमें कई परतें होंगी। इसलिए इस बारे में स्पष्ट जवाब देना बहुत मुश्किल है।

राकेश सूद: मिस्र, हम इसे फिलहाल छोड़ सकते हैं। वरना, हमारे पास पहले ही समय कम पड़ रहा है। ठीक है।

राजीव नयन: तो सऊदी अरब-पाकिस्तान समझौते के बारे में, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान सऊदी अरब को परमाणु हथियार देने की हिम्मत करेगा। अगर ऐसा होता है, तो यह पूरी तरह से अलग मामला होगा। तो वे हैं, समझौता सुरक्षा, परमाणु, नया न्यूक्लियर अंब्रेला देने के बारे में है। ऐसे कई न्यूक्लियर अंब्रेला आ रहे हैं। मेरा मतलब है, यूरोपीय देशों के पास एक अलग तरह का न्यूक्लियर अंब्रेला है। फ्रांस इसका नेतृत्व करेगा, यही सामने आ रहा है और इस पर काम चल रहा है और यूरोपीय महाद्वीप के कई प्रमुख टिप्पणीकार, लेखक और विचारक इस विषय पर काम कर रहे हैं। यूरोपीय रक्षा या यूरोपीय परमाणु निवारक संरचना का स्वरूप क्या होगा? यह बहुत दिलचस्प होगा। कई देश, जिन्हें बहुत शांतिपूर्ण और शांतिप्रिय माना जाता है, इस निवारक संरचना में योगदान देंगे। यह एक बात है। सीमा कब पार करनी है? मुझे लगता है कि यह एक कठिन सवाल है और आम तौर पर, जब तक आप पर हमला नहीं होता, चाहे जो भी सामने आ रहा हो, आप इसका इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करेंगे, चाहे लोग इसे पसंद करें या नहीं। मेरा मानना है कि नीना टैननवाल्ड का परमाणु निषेध का सूत्रीकरण बहुत प्रभावशाली है और इसे

कई लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया है, लेकिन जब आप किसी परमाणु प्रतिशोध की उम्मीद नहीं कर रहे होते हैं, तब भी आप दुनिया में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका या रूस ने वास्तव में कितनी बार परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया है? तो मुझे लगता है कि यही स्थिति है। इसके परिणाम काफी विनाशकारी होंगे और पाकिस्तान ने भी कई बार शोर मचाया, लेकिन अंततः उसने सिर्फ शोर मचाया। उसने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कर सका क्योंकि उसे पता है कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, खासकर एक परमाणु हथियार संपन्न देश के लिए। इसलिए मुझे लगता है कि यही वह सीमा है जिस पर मैं विचार कर रहा हूँ। यह एक लंबी बहस है। परमाणु ऊर्जा के कई दौर, कई युग आए और गए, इसलिए वे सभी इस सवाल का जवाब तलाशने में संघर्ष कर रहे हैं। तो, मेरा मतलब है, महोदया, मैं आपका प्रश्न समझ नहीं पाया। कोई बात नहीं।

राकेश सूद: कोई और सवाल? हाँ। यह आखिरी दौर है।

अज्ञात वक्ता: बहुत-बहुत धन्यवाद, महोदय। बहुत ही उपयोगी चर्चा हुई। पैनल चर्चा से, मैं जो देख और समझ पाया, वह यह है कि न्यूक्लियर फ्लक्स था। यह आगे भी बना रहेगा और वैश्विक राजनीति की गतिशीलता इस पर आगे प्रभाव डाल भी सकती है और नहीं भी। अब मेरा प्रश्न श्री राजीव द्वारा बताए गए मुद्दे से शुरू होता है, यह एक अलग सवाल है। आप उभरती हुई तकनीकों की बात कर रहे हैं, आप बहुत जल्दी स्वीकार कर रहे हैं कि जब तक मानव हस्तक्षेप मौजूद है, कमान की श्रृंखला स्थापित की जा सकती है और ऐसा करना सही है। क्या आपको लगता है कि घातक स्वायत्त हथियार प्रणाली जैसी उभरती हुई तकनीकें, उदाहरण के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के स्थापित नियमों का पालन करेंगी?

राकेश सूद: मानवीय कानून ने अभी तक परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। हम न्यूक्लियर फ्लक्स की बात कर रहे हैं, क्या हम एक और सवाल पूछ सकते हैं?

अनुराग द्विवेदी: पैनलिस्टों, आपकी शानदार टिप्पणियों और व्यापक अंतर्दृष्टि हेतु बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अनुराग द्विवेदी है, मैं कूटनीति और निरस्त्रीकरण पर काम कर रहा एक डॉक्टरेट का छात्र हूँ, मैं सीआईपीओडी जेएनयू से हूँ। तो प्रोफ़ेसर राजेश राजगोपालन के विचारों पर गौर कीजिए। मैं प्रोफ़ेसर से पूछना चाहता हूँ, आपने बताया कि दुनिया द्विध्रुवीय होगी, लेकिन आपने कहा कि परमाणु ऊर्जा के मामले में यह त्रिध्रुवीय होगी, तो त्रिध्रुवीय में बहुध्रुवीय शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया गया, जबकि परमाणु ऊर्जा दो और तीन से भी ज़्यादा है। तो फिर यह बेंजामिन जैसे विद्वानों की तरह बहुध्रुवीय क्यों नहीं है...

राकेश सूद: आपका सवाल मैं समझ गया।

अनुराग द्विवेदी: एक और सवाल, माफ़ कीजिए, एक और सवाल।

राकेश सूद: वह आपके प्रोफ़ेसर हैं, आप उनसे विश्वविद्यालय में ये सवाल पूछ सकते हैं।

अनुराग द्विवेदी: और राजदूत राकेश से एक सवाल, महोदय, जैसा कि आप प्रोफेसर राजेश राजगोपालन की बातों से समझ रहे हैं, आप कैसे देखते हैं, जैसे दुनिया परमाणु ऊर्जा के मामले में द्विध्रुवीय और बहुध्रुवीय होने जा रही है, आप भविष्य में निरस्त्रीकरण की गतिशीलता को कैसे देखते हैं? जैसा कि हमने देखा है, जैसा कि मौरर ने अपनी पुस्तक "कॉम्पिटिटिव आर्म्स कंट्रोल" में कहा है कि शीत युद्ध के दौरान सहयोगात्मक हथियार नियंत्रण के बजाय प्रतिस्पर्धी हथियार नियंत्रण ज़्यादा था। तो चूँकि आपने निरस्त्रीकरण पर काम किया है, आप इस बात का हिस्सा रहे हैं कि आप भविष्य को कैसे देखते हैं, आप भविष्य में निरस्त्रीकरण की पहल को कैसे देखते हैं।

राकेश सूद: धन्यवाद। क्या किसी और का यहाँ कोई सवाल है? नहीं? ठीक है, ठीक है। माफ़ कीजिए, आपका सवाल ईरान के बारे में था। ईरान अपनी सुरक्षा हेतु परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, बस इतनी सी बात है। और जो भी दूसरा देश ऐसा करता है, वह अपनी सुरक्षा के लिए करता है। सभी ने यही किया है।

राजेश राजगोपालन: हाँ, चूँकि आपने पूछा है। हम जेएनयू में इस पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मेरा मतलब है, मुद्दा यह है कि, नहीं, मेरा मतलब ध्रुवीयता की अवधारणा में त्रिध्रुवीयता से नहीं था, मेरा मतलब है, त्रिध्रुवीयता का मतलब बस तीन देशों के पास लगभग समान संख्या में परमाणु हथियार होना था क्योंकि चीन उस स्तर तक पहुँच जाएगा, मेरा बस इतना ही मतलब था। मेरा मतलब ध्रुवीयता से नहीं था, ध्रुवीयता शब्द के आईआर सिद्धांत के अर्थ में, ठीक है।

राकेश सूद: ठीक है। आपके पास, हमारे पास आपके लिए और...के लिए दो मिनट हैं।

राजीव नयन: इसमें बस एक मिनट लगेगा। महोदया, मैंने पहले ही सवाल का उत्तर दे दिया है। जैसे, इसमें कुछ तत्व हैं, मानवीय तत्व तो होंगे ही, भले ही आप घातक स्वायत्त हथियार प्रणाली की बात कर रहे हों। दरअसल, निरस्त्रीकरण सम्मेलन में इस बारे में बात हुई थी, और वह यह है कि यह कुछ पारंपरिक हथियारों पर कुछ पारंपरिक सम्मेलनों के अंतर्गत आता है। तो इस पर बात हो रही है और फिर से, मूल समस्या परिभाषा की है। अगर आप इससे शुरुआत करते हैं, तो अन्य तत्व भी हैं। और कोई भी लेख इस बात से इनकार नहीं करता कि एल्गोरिथम इंसान नहीं बनाएगा। यह मशीन बनाएगी। तो यह बात तो है। तो मैं - हम इस बारे में बात कर सकते हैं। मैंने - और यह ज़्यादा लंबी है क्योंकि मुझे - बस मुझे सिर्फ़ एक मिनट दिया गया है।

राकेश सूद: तो मुझे महानिदेशक की बातों को मानना होगा। अगर आपको कुछ कहना है तो आपके पास एक मिनट है, या हम धन्यवाद प्रस्ताव हेतु आगे बढ़ सकते हैं।

रेशमी काज़ी: बस एक बात। हम परमाणु युग के 80वें वर्ष में हैं। हम परमाणु युग के 80वें वर्ष में हैं। तो यह वह युग नहीं है जहाँ हम सचमुच हथियारों की दौड़ में शामिल हो सकें। मुझे लगता है कि यह दौड़ तर्कसंगतता की है। और जैसा कि रॉबर्ट मैकनामारा ने अपने 1960 के फ्रांसिस्को भाषण में कहा था, हम सभी को तर्कसंगतता की उस दौड़ में शामिल होना चाहिए। धन्यवाद।

मुकेश कुमार: इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज की चर्चा ज्ञानवर्धक और विचारोत्तेजक रही और इससे हमारा ज्ञान व दृष्टिकोण काफी बढ़ा। आईसीडब्ल्यूए की ओर से, मैं सम्मानित अध्यक्ष और पैनलिस्टों के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ। आईसीडब्ल्यूए की कार्यवाहक महानिदेशक सुश्री नूतन कपूर महावर और परिषद में अनुसंधान निदेशक सुश्री निवेदिता रे को उनके निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन हेतु मेरा विशेष धन्यवाद। मैं अपने सभी सहयोगियों और श्रोताओं को भी उनकी भागीदारी के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। आईसीडब्ल्यूए के शोध कार्यों, आयोजनों, आउटरीच कार्यक्रमों और प्रकाशनों के बारे में अधिक जानने के लिए, हमारी वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल, ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक और यूट्यूब पर अवश्य जाएँ। धन्यवाद, और कृपया फ़ोयर में हमारे साथ हाई टी हेतु जुड़ें। धन्यवाद।

-x-x-x-x-x-x-